



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1985/माघ 27, 1906

No. 41]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1985/MAGHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रखी जा जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

सहायता की सिफारिश किए जाते समय, आयोग
द्वारा उस तारीख का भी उल्लेख कर दिया जाए जिस
तारीख से यह राहत दी जानी है।”

आवेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में
प्रकाशित कर दिया जाए।

सं. 5 (56) संस्था 3/83 :—भारत सरकार ने यह निर्णय किया
है कि इस मंत्रालय के विनांक 29 जुलाई, 1983 के समसंख्यक
संकल्प में दिए गए चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ
विषयों में उक्त संकल्प के पैरा 2 के अन्तर्गत एक नया उप-पैरा
(5) जोड़ कर निम्न प्रकार संशोधन किया जाएगा :—

“(5) यदि आयोग के विचार-विमर्श की अवधि के दौरान
अन्तरिम प्रकार की राहत पर विचार किए जाने की
आवश्यकता पड़े तो आयोग अन्तरिम प्रकार के राहत
की मांग पर विचार कर सकता है और वित्त मंत्रा-
लय (व्यय विभाग) के विनांक 2 अगस्त, 1983 के
का. आ. सं. 7(39)/संस्था. 3/83 में सरकार
द्वारा पहले से स्वीकृत की गई अन्तरिम राहत को
ध्यान में रखते हुए उस पर अपनी सिफारिशें कर
सकता है। आयोग द्वारा किसी प्रकार की अन्तरिम

यह भी उपदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति चतुर्थ
केन्द्रीय वेतन आयोग- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य
सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों और अन्य सभी
संबंधितों को भेज दी जाए।

एस. वेंकटरमणन्, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Expenditure

RESOLUTION

New Delhi, the 16th Feb., 1985

No. 5(56)-E.III|83.—The Government of India
have decided that the Terms of Reference of the
Fourth Central Pay Commission as contained in this
Ministry's Resolution of even number dated the 29th

July, 1983 shall be amended by addition of a new sub-para (5) under para 2 of the Resolution as under :—

“(5) In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of interim character and make its recommendations thereon taking into account the interim relief already sanctioned by the Government in the Ministry of Finance (Depot. of Expenditure's) O.M. No. 7(39)/E.III/83 dated the 2nd August,

1983. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief should take effect may also be indicated by the Commission.”

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Fourth Central Pay Commission, Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

S. VENKITARAMANAN, Secy.